



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2014/आश्विन 4, 1936

No. 504]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2014/ASVINA 4, 1936

गृह मंत्रालय

(स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 695(अ).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 613(अ), के अंतर्गत अधिसूचित भारत के शत्रु संपत्ति उप-अभिरक्षक पद के लिए एतद्वारा विद्यमान भर्ती नियमों में मुद्रण संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करते हैं : —

‘विद्यमान भर्ती नियमों में कालम 11 में प्रतिनियुक्ति संबंधी पात्रता शर्तों को विद्यमान प्रावधानों के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है: —

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय सरकार के वे अधिकारी जो

(क) (i) मूल संवर्ग में सदृश पद धारण किए हुए हैं

या

(ii) वेतन बैंड-3 (15,600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं

या

(iii) वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4800 रु. में छः वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं

या

(iv) वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4600 रु. में सात वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं।

- टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य संवर्ग में धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण 3 :** समान ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में एक ग्रेड में एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का आमेसन और जहां यह लाभ केवल उन्हीं पद (पदों) के लिए होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं, को छोड़कर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान की गई है) वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदत्त समनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवाओं के समान मानी जाएगी।

[फा.सं. 37/17/2008-ई.पी.]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Freedom Fighters and Rehabilitation Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2014

G.S.R. 695(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments to correct the typographical errors in the existing Recruitment Rules for the post of Deputy Custodian of Enemy Property notified vide Notification No. G.S.R 613(E), dated 30th July, 2012:—

“The eligibility conditions for deputation in Col. 11 of the existing Recruitment Rules are substituted as under in place of the existing provisions: —

Deputation:

Officers of the Central Government

- (a) (i) holding analogous posts in the parent cadre
or
(ii) with five years regular service in pay band-3 (Rs. 15600-39100) and grade pay of Rs. 5400/-
or
(iii) with six years of regular services in pay-band-2 (Rs. 9300-34800) and grade pay of Rs. 4800/-
or
(iv) with seven years of regular service in pay band-2 (Rs. 9300-34800) and grade pay of Rs. 4600/-

Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 3. For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommended has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.”

[F. No.37/17/2008-EP]

K.K.PATHAK, Jt. Secy.